साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 29 अगस्त- 04 सितंबर 2022, वर्ष-8, अंक-21

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

गांव में 400 ट्रक, 800 ड्राइवर, सीजन के चार माह में देशभर में 4000 ट्रक भूसा सप्लाई

कारोबार का फॉर्मूला

फसल लगते ही जिलों में सर्वे पर निकल जाते हैं गांव के लड़के

देश में जहां भी अकाल या चारे का संकट होता है, वहां भोपाल का ललरिया गांव करता है भूसे की आपूर्ति

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल जिले की बैरसिया विधानसभा सीट का 10 हजार की आबादी वाला गांव है ललरिया। लेकिन ये छोटा सा गांव पूरे देश के मवेशियों की भूख मिटाने के लिए हमेशा संकट मोचक साबित होता है। वो इसलिए, क्योंकि देश में जहां भी अकाल या चारे का संकट होता है, ललरिया ही वहां भूसे की आपूर्ति करता है। यहां के लोग आसपास के इलाकों से पूरा भूसा खरीदकर स्टॉक करते हैं और दोगुनी कीमत पर उसे देशभर में जरूरत पड़ने पर भेजते हैं। यहां मप्र का दूसरा सबसे बड़ा भूसा सप्लायर सेंटर है। पहले नंबर पर सागर जिले का खुरई है। ललरिया में बीते 10 साल में भूसे का कारोबार इतना बढ़ गया है कि यहां का सालाना टर्नओवर 60 से 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

सरपंच भूसे के बड़े कारोबारी

पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे अब्दुल हकीम का परिवार तीन पीढ़ियों से भूसे के कारोबार से जुड़ा है। वे बताते हैं कि गांव के लड़के खड़ी फसल के दौरान ही आसपास के जिलों में सर्वे करने निकल जाते हैं और भूसे का सौदा कर एडवांस दे आते हैं। फसल कटाई के वक्त दूसरी टीम भूसा लेने पहुंच जाती है। यदि बाहर से डिमांड आती है तो सीधे सप्लाई कर दिया जाता है। ललरिया गांव के सरपंच मोहम्मद सादिक खान खुद भूसे के बड़े कारोबारी हैं। उनके मुताबिक गांव में 250 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के ट्रक हैं। कुल ट्रक 400 हैं। 800 ट्रक ड्राइवर हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे नियमित मजदूर हैं, जो भूसा लोडिंग-अनलोडिंग के विशेषज्ञ हैं।

चंबल अंचल में बढ़ी डिमांड

बैरसिया में बायो फ्यूल कंपनियों के प्लांट हैं, जो सड़े भूसे से बायो फ्यूल (कच्चा कोयला) बनाती हैं, जो मंडीदीप के उद्योगों में सप्लाई होता है। कारोबारी दीपक खत्री बताते हैं कि पुणे के मशरूम उत्पादक, गुजरात के गौशाला संचालक और राजस्थान के डेयरी कारोबारी हमारे सबसे बड़े खरीदार हैं। इंदौर, ग्वालियर, भिंड और मुरैना से भी डिमांड बढ़ी है।

500 रुपए क्विंटल रही भूसे की खरीदी

भूसे का सीजन मार्च से जून तक चलता है। इस दौरान चार महीने में 4 हजार ट्रक भूसा देशभर में सप्लाई करते हैं। इसके बाद गांव में स्टोर भूसे को सालभर में डिमांड आने पर सप्लाई करते रहते हैं। गांव में भूसा बनाने वाली रीपर मशीनें, जेसीबी, ट्रैक्टर सहित कई आधुनिक उपकरण हैं। सादिक बताते हैं कि इस साल गेहूं के भूसे की खरीदी औसतन 500 रुपए प्रति क्विंटल रही। प्रदेश में इसकी बिकवाली 1000 रुपए प्रति क्विंटल और पुणे व राजस्थान में 1400 रुपए प्रति क्विंटल रही।

कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह बोले

सीएम ने कहा-सबको साख-सबका विकास मप्र में सहकारिता का मूल मंत्र

भारत में कॉरपोरेट होगी 'को-ऑपरेटिव खेती'

- सहकारी समितियों को बहुद्देश्यीय बनाने केंद्र सरकार एक महीने में लाएगी माडल एक्ट
- केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर बोले-भारत के संस्कार में सहकार शामिल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में शीघ्र ही कॉरपोरेट खेती के स्थान पर कोऑपरेटिव खेती होगी। केन्द्र सरकार शीघ्र ही नई सहकारिता नीति ला रही है। देश में सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा। पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में केंद्र सरकार आगामी एक माह में एक्सपोर्ट हाउस बनाने जा रही है। अमूल कुछ ही समय में देश में मिट्टी का परीक्षण एवं किसानों के उत्पाद का परीक्षण कर उन्हें जैविक प्रमाण-पत्र 'अमूल' के नाम से देगा। इससे किसानों को अपनी फसलों का अधिक मूल्य मिलेगा और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल प्रवास के दौरान नाफेड द्वारा आयोजित कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। उन्होंने एक जिला-एक उत्पाद योजना में मप्र के 11 जिलों के 11 उत्पादों के साथ देश के 6 अन्य राज्यों के उत्पादों का भी प्रमोशन किया। शाह ने सहकार से समृद्धि-51 कहानियां पुस्तक एवं सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग-1 एवं 2 का विमोचन भी किया।

- मप्र के 11 जिलों के 11 उत्पादों के साथ देश के 6 राज्यों के उत्पादों का प्रमोशन
- किसानों को फसलों के मूल्य के साथ प्राकृतिक व जैविक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

तीन लाख के कर्ज पर मिलेगा अनुदान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबको साख-सबका विकास मप्र में सहकारिता का मूल मंत्र है। इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मप्र में सहकारिता का इतिहास 118 वर्ष पुराना है। वर्ष 2012-13 से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। केंद्र ने फैसला किया है कि शीघ्र ही 3 लाख रुपए तक अल्पावधि फसल ऋण पर डेढ़ प्रतिशत अधिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सरकार नई सहकारिता नीति बनाने जा रही है। प्रदेश में सहकारिता को स्व-रोजगार दिलाने का साधन बनाया जा रहा है। परम्परागत कारीगरों को सहकारी समिति के रूप में संगठित कर उनका कौशल संवर्धन किया जा रहा है। सहकारिता कानूनों में बदलाव एवं सरलीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के संकल्प को पूरा करने में सहकारिता की अहम भूमिका है।

भारत को आत्म-निर्भर बनाएं

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत के संस्कार में सहकार शामिल है। जितना सहकार बढ़ेगा उतनी ही देश प्रगति करेगा औरदेश की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारिता को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने भारत में पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और नाफेड को कर्ज से बाहर निकाला। इफको एवं अमूल दुनिया के सबसे बड़े सहकारिता संगठन है। सहकारिता से जुड़ कर हम स्वयं एवं भारत को आत्म-निर्भर बनाएं।

मप्र में समर्थन मूल्य पर मूंग का उपार्जन

15 दिन में सिर्फ 1262 टन मूंग की खरीदी

जबलपुर। जागत गांव हमार

जिले में मूंग खरीदी चल रही है। इस काम की गति और उपार्जन नीति की सार्थकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 दिनों की खरीदी के बाद उपार्जन का आंकड़ा 1262 मीट्रिक टन तक ही पहुंच पाया। जिम्मेदारों का मानना है कि किसानों के पास बहुत ज्यादा मूंग नहीं बची है। इसलिए उपार्जन के आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद को लेकर किसान महीनों परेशान रहे। जैसे-जैसे सरकार की ओर से आठ अगस्त से मूंग का उपार्जन शुरू हुआ। उम्मीद रही कि किसान अनी उपज लेकर खरीदी केंद्रों पर उमड़ पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कहीं देखा नहीं जा रहा। जिले में 13485 किसानों ने मूंग विक्रय के लिए पंजीयन कराया था। जिनमें से अब तक केवल 699 किसान ही खरीदी केंद्रों तक पहुंच पाए। पूरे जिले में प्रशासन की ओर से 19 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उपार्जन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है।

अव्यवहारिक रूप से बने केंद्र

मूंग-उपार्जन को लेकर जो नीति बनाई गई, उसमें अनेक प्रकार की खामियां रहीं। शासन का कहना रहा कि किसी भी किसान को उपज बेचने के लिए 25 किमी से ज्यादा दूर न जाना पड़े। लेकिन बरसात में ऐसा करना किसानों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मझौली, पाटन और चरगवां के अनेक किसान खरीदी केंद्र 30 किमी दूर होने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार इस मामले में सहयोग कर पाने में खुद को असमर्थ बता रहे है।

- सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 7275 रुपए तय कर रखा है। वर्तमान में खुले बाजार में मूंग का रेट पांच हजार के बीच है। किसान मूंग देर-सवेर खरीदी केंद्र पर ही बेचने आएंगे। किसान डेढ़ से दो हजार रुपए क्विंटल का नुकसान नहीं उठाएगा।

एसके निगम, उप संचालक, कृषि विभाग

- जिले में 19 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर करीब एक हजार किसानों से खरीदी का इंतजाम है। उपार्जन प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। अब तक 699 किसानों से 1262 मीट्रिक टन का उपार्जन हुआ है।

-रोहित सिंह बघेल, डीएमओ

विधिवत अनुबंध के अभाव में लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा

अधिनियम 2016 है भूमि स्वामी और बटाइदारों के लिए उपयोगी

भोपाल। जागत गांव हमार

जिले में भूमि स्वामियों और बटाइदारों के लिए अधिनियम 2016 उपयोगी है। सामान्य तौर से किसानों और भूमि स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को धन या फसल का अंश भूमि स्वामी को देकर खेती के लिए दी जाती है। जिसे सामान्य तौर पर बटाई, सिकमी अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। इस संबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम भूमि स्वामी बटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है। अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी। जब दोनों पक्षों के द्वारा मप्र भूमि स्वामी बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बटाईदार, भूमि बटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा। जब भूमि स्वामी और बटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो। विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नही होगा।

एप पर पात्रता की जानकारी

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। तैनात कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। उपभोक्ता भी गूगल प्ले स्टोर से इस एप को स्टाल कर सकते हैं इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सिवनी-मालवा में खरीदी केंद्रों का कृषि मंत्री ने किया निरीक्षण

किसानों को फसल का पूरा पूरा लाभ दिलाने सरकार संकल्पित

भोपाल। जागत गांव हमारा

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल का पूरा-पूरा लाभ दिलाने के लिए कृत-संकल्पित है। मंत्री पटेल ने सिवनी-मालवा जिले के ग्राम हरपालपुर के वेयर हाउस खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मूंग तुलाई का भी अवलोकन लिया। मंत्री ने केंद्र पर उपज बेचने आए किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की पड़ताल भी की। किसानों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कृषि मंत्री का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में किसानों को आवश्यक सुविधाओं के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7275 रुपए के समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने से किसान बहुत खुश हैं। उन्हें लगभग 2 हजार रुपए क्विंटल का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्रीष्मकालीन मूंग के अतिरिक्त चना, मसूर एवं सरसों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की गई है। किसानों को उनकी मेहनत का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है।

किसानों को हो रहा लाभ

किसान जितेंद्र चौहान ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी एवं किसान हितैषी नीतियों के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पूर्व में ग्रीष्मकालीन मूंग मात्र 5 से 5 हजार 500 रुपए तक बिकने से किसानों को नुकसान हो रहा था। सरकार द्वारा 7275 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने से किसानों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। किसान बहुत खुश हैं, क्योंकि मूंग फसल के लिए नहरों में पर्याप्त पानी देना हो या फसल बीमा क्लेम की राशि, किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं।

किसानों को दिया जाएगा माली प्रशिक्षण

संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण द्वारा किसानों के लिए माली विषयक सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में राज्य पोषित योजना कृषक प्रशिक्षण-सह-भ्रमण में इच्छुक कृषकों का कौशल उन्नयन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आगामी वर्ष में विभाग में कुशल श्रमिक, मालियों की भर्ती में प्रशिक्षित एवं तकनीकी रूप से योग्य उम्मीदवार प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण की अवधि 200 घंटे (25 दिवस) तय की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 30 कृषक का चयन किया जाना है। उद्यानिकी में रुचि रखने वाले इच्छुक कृषक, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं हो, प्रशिक्षण के लिए अपना पंजीयन जिले के उद्यानिकी कार्यालय में करा सकते हैं। कृषकों का चयन निर्धारित लक्ष्य एवं प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा।

सर्वोत्तम किसान और समूह 31 अगस्त तक करें आवेदन

-अन्य किसी और तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा

भोपाल। आत्मा परियोजना के तहत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि यंत्रिकरण के क्षेत्र में जिला व विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम किसान एवं किसान समूह को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए परियोजना संचालक आत्मा के कार्यालय में 31 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। परियोजना संचालक आत्मा के अनुसार विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार के तहत 10 हजार रुपए, सर्वोत्तम किसान समूह के पुरस्कार के तहत 20 हजार और जिला स्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार के तहत 25 हजार का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए इच्छुक किसान एवं किसान समूह अपने-अपने आवेदन संबंधित जनपद पंचायत के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। पुरस्कारों के चयन में कलेक्टर सह अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला परियोजना संचालक आत्मा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

ई खसरा-खतौनी ही लें किसान

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर ने ई-खसरा परियोजना को लागू किया है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वह ई खसरा-खतोनी ही लें। इस परियोजना के अंतर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसील में आइटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। जिनसे किसानों को उनकी मांग अनुरूप प्रमाणतिखसरा बी-1, नक्शा की प्रतिलिपियां नियत शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपए लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। किसान अपने खाते की नकल, खेत का अक्श विभागीय बेवसाईट पर एक दम निशुल्क देख सकते हैं। साथ ही उपयोग के लिए यहां से अपनी भूमि के खसरा-खतौनी, नक्से का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। यह प्रिंट सिर्फ जानकारी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इनका अन्य किसी और तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

छात्रों और उद्यमियों के लिए आईसीएआर की पहल

'कृतज्ञ' से किसान जीत सकते हैं 5 लाख तक का इनाम

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) का फसल विज्ञान संभाग और राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना राष्ट्रीय स्तर का एग्रीटेक हैकाथॉन कृतज्ञ का आयोजन कर रहे है। देशभर के विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के विद्यार्थी, संकाय और उद्यमी एक समूह के रूप में इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों संकायों उद्यमियो नव प्रवर्तनकर्ताओं और अन्य लोगों को भारत में फसल उत्पादन और फसल सुधार के लिए प्रोत्साहित करेगा। आईसीएआर के फसल विज्ञान प्रभाग के साथ एनएएचईपी के तहत इस तरह की पहल से फसल विज्ञान क्षेत्र में सीखने की क्षमता, नवाचार और विघटनकारी समाधान, रोजगार और उद्यमशीलता अभियान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवेदक फसल सुधार के बहुत विशिष्ट मुद्दों जैसे कि तेजी से उत्पादन ऊन्नति सुविधाओं के लिए सस्ती और अधिक प्रभावी सामग्री, रोगों के लिए सटीक और आसान निदान उपकरण, कीट कीट, उपज की गुणवत्ता आदि पर संभावित समाधान प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन फसल विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों या प्रथाओं के अनुप्रयोग का लाभ उठाकर नवीन, विघटनकारी और आउट ऑफ बॉक्स समस्या समाधान प्रस्तावों के साथ आवेदकों को आमंत्रित और प्रोत्साहित करेगा। समस्या विवरण और समाधान स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट पर केंद्रित होंगे। देशभर के विवि, तकनीकी संस्थान के विद्यार्थी, संकाय और उद्यमी एक समूह के रूप में इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इस समूह में अधिकतम 4 प्रतिभागी होंगे, जिसमें एक से अधिक संकाय-सदस्य और या एक से अधिक नवोन्मेषक अथवा उद्यमी नहीं होगा. प्रतिभागी विद्यार्थी, स्थानीय स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों के साथ सहयोग में हो सकते हैं। वे इसमें 5 लाख रुपये तक जीत सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 26 अगस्त से शुरू हो चुका है।

जोनल स्तर पर चयन

अवधारणा प्रविष्टियों की सभी स्क्रीनिंग प्रारंभिक चरण में की जाएगी, इसके बाद तकनीकी प्रस्तुति के माध्यम से जांचे गए विचारों का क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक जोन से, 3 विजेताओं का चयन राष्ट्रीय दौर के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय दौर की बेहतर तैयारी के लिए क्षेत्रीय स्तर के विजेताओं को डोमेन विशेषज्ञों से मेंटरशिप का समर्थन मिलेगा। जोन स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित।

राष्ट्रीय स्तर पर चयन इस दौर के तहत जोनल स्तर के विजेता राष्ट्रीय स्तर की समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देंगे और 3 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के रूप में चुना जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के विजेताओं को नकद पुरस्कार और भागीदारी प्रमाण पत्र के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

शिवराज ने संभाला मोर्चा: कहा-फसल बीमा की राशि भी दिलाई जाएगी

चिंता मत करना सबको मिलेगी राहत

» सीएम पहले नाव से और फिर घुटने तक पानी में पैदल चल कर बस्ती में पहुंचे

» प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के मकानों और फसलों का प्राथमिकाता से होगा सर्वे

» सड़क, पुल, बिजली और स्वच्छता के काम प्रारंभ करने के दिए निर्देश

भोपाल। जागत गांव हमार

बाढ़ में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के बाद अब व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के काम युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के साथ स्वच्छता के काम प्राथमिकता पर होंगे। क्षतिग्रस्त मकान और फसलों को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराकर आर्थिक सहायता दी जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से हुई क्षति की व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार को लेकर आयोजित बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा थमने के बाद पानी उतरने लगा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्य में पुलिस, प्रशासन, होमगार्ड की टीम लगी हुई हैं। कई जगह सड़क, पुल, पुलिया को नुकसान पहुंचा है। बिजली और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसे युद्ध स्तर पर दुरुस्त करना है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद स्वच्छता का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। बाढ़ और अतिवृष्टि से मकान, घरेलू समान और फसलों को नुकसान हुआ है।

इसका आकलन पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ किया जाएगा। नुकसान के आकलन में गरीब परिवारों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखें। उन्होंने जिला प्रशासन को बाढ़ से अत्याधिक प्रभावित परिवारों के लिए कुछ दिनों के भोजन की व्यवस्था करने और बाद में सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी। वहीं, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बांधों की स्थिति के बारे में बताया।

चंबल अंचल के 100 गांव प्रभावित मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुरैना, भिंड और श्योपुर के लगभग 100 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। संकट, मुश्किल और परेशानियां भी हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस घड़ी में सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद करेगी। प्रभावित क्षेत्रों में जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण करा कर भरपाई की जाएगी।

आपदा में कोई मतभेद मत करना

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के तत्काल बाद नुकसान का सर्वे करवाया जाएगा। जिनके घर गिर गए हैं, उनको घर निर्माण के लिए भी राशि दिलाई जाएगी। जिनकी घर-गृहस्थी का सामान बह गया है और अनाज का नुकसान हुआ है, उन्हें भी पूरी मदद दिलाई जाएगी। चिंता न करें बाढ़ पीड़ितों को संकट के पार निकाल कर उनकी हर संभव मदद की जाएगी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वे होगा। सर्वे की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करवाई जाएगी। किसी को आपत्ति होने पर उसकी सुनवाई भी होगी। आपदा में कोई मतभेद या भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को मिल कर विषम परिस्थिति का सामना करना चाहिए।

चिंता मत करना मैं खड़ा हूं

मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले कुरवाईवासियों से कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर रहे। आपके साथ आपका मुख्यमंत्री खड़ा है। आपकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ राहत केंद्र में आवश्यक सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रभावितों को भोजन, चाय-नाश्ता, पेयजल सभी उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कुरवाई में वार्ड 3, पटेल ढाबा, बिजली ऑफिस सहित अन्य स्थानों का जायजा लिया एवं वहां रह रहे बाढ़ पीड़ितों को सांत्वना दी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

ग्वालियर में वर्षा की स्थिति की ली जानकारी

मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेने के बाद रात्रि लगभग 11.15 बजे ग्वालियर विमानतल पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर ग्वालियर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर ग्वालियर जिले में हुई वर्षा के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांधों एवं नदियों के बढ़ते जल स्तर पर नजर रखें और एहतियात बतौर बाढ़ एवं अतिवृष्टि से निपटने के लिए 24 घंटे पुख्ता इंतजाम रहें। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि जिले में अभी तक लगभग 503 एमएम औसत वर्षा हुई है।

पादर्शिता के साथ हो सर्वे

मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से मुरैना पहुंचे और मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर अंबाह के समीप ग्राम कुथियाना पहुंचे। राहत कैम्पों में रह रहे लोगों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने प्रभावितों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी सरकार और मैं स्वयं भी आपके साथ संकट की इस घड़ी में खड़ा हूं। प्रभावितों की मदद के लिये स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य किए जाएंगे। शीघ्र ही जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण का कार्य पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ किया जाए।

नुकसान का आकलन होगा

सर्वेक्षण में न केवल मकान बल्कि पशु, खाद्य सामग्री एवं फसल का भी सर्वेक्षण कराया जाए। सर्वेक्षण के आधार पर जो भी नुकसान का आकलन होगा वह प्रभावितों को राज्य सरकार प्रदान करेगी। जिन गांवों में हर वर्ष या बार-बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उन गांव के निवासियों की सहमति के आधार पर उन्हें ऊंचे स्थान पर बसाने का कार्य भी किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर लोगों को आवास निर्माण में मदद दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी चर्चा हुई है, वे स्वयं भी आएंगे। केन्द्र और प्रदेश सरकार आपकी मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

ऊंचे स्थानों पर बनवाएं घर

मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाह से कहा कि वे ऐसे बाढ़ प्रभावित गांव जहां बार-बार बाढ़ का पानी भर जाता है, उन्हें ऊंचे स्थान पर बसाने के लिए आम सहमति बनाने की कार्रवाई प्रशासन के सहयोग से कराएं। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों से कहा है कि बाढ़ का पानी जब तक उतर नहीं जाता है, तब तक राहत कैम्पों में ही रहें।

चिंता न करे संकट से उबार कर ले जाऊंगा

मुख्यमंत्री ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित जतरापुरा की करीब 250 घरों की बस्ती में पहुंच कर बाढ़ प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री पहले नाव से और फिर घुटने तक पानी में पैदल चल कर बस्ती में पहुंचे। जतरापुरा से लगी हुई राजीव गांधी आवास योजना की यह बस्ती बेतवा के बेक वाटर और एक स्थानीय नाले के कारण जलमग्न हो गई थी। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बस्ती के महिला, पुरूष और बच्चों में नई चेतना जाग्रत हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने मन की बात कही। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि चिंता की बात नहीं है, जल्दी ही सभी को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी बचाना हमारी पहली प्राथमिकता थी और अब जैसे-जैसे पानी कम हो रहा है, सभी मूलभूत सुविधाओं को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भोजन और अन्य सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध कराए।

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास

अशोक कुमार पांडेय
व्यवस्थापक, विद्या भारती एवं समाज सेवी

मनुष्य का जीवन प्रतिभाओं का भंडार है और यदि किसी भी मनुष्य के आधारभूत गुणों या ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाओं का पूर्ण सदुपयोग उसके जीवन में नहीं किया जाता तो प्रतिभाएं व्यर्थ ही हो जाती हैं। हम अपने बाल्यकाल से एक ऐसी शिक्षा पद्धति की छत्र-छाया में पले-बढ़े जिसमें सब विद्यार्थी एक-दूसरे की देखादेखी कोर्स का चयन करते थे, न उनकी प्रतिभाओं का आकलन शिक्षक करते थे, न ही अभिभावकों की ही दूरदृष्टि इस ओर जाती थी, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या साधारण ग्रेजुएट होकर नौकरी ढूंढ़ने की प्रथा थी।

कुछ लोग सेना में या प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं देकर सरकारी नौकरियों में चले जाते थे। न तो मार्गदर्शन किया जाता था कि कैसे अपने गुण या प्रतिभाओं का आकलन करके सही दिशा की ओर जीवन को ले जाना चाहिए, न ही विद्यार्थियों के पास इतना समय था कि वो इस ओर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकें। वस्तुतः सारा शिक्षण का ढांचा ही कुछ इस प्रकार था कि अधिकांशतः युवा वर्ग दिशाहारा था। शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी थी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न करती थी-मूल चिंतन और विचारधारा के विकास में अवरोध, काल्पनिक और नए वैचारिक और मानसिक शक्ति के विकास में अवरोध, मनुष्य की मूलभूत प्रतिभाओं के विकासीकरण में अवरोध। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए और सजग, विचारशील और नवीनतम आयामों को ग्रहण करने वाले एक सशक्त युवा वर्ग के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था कि विषयों की जानकारी के साथ-साथ बच्चे समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, नया सोचें, अपने विचारों को विस्तृत करें। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित, जिज्ञासा, खोज, संवाद के आधार पर लचीली हो, समग्र हो। शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास जिसे साक्षरता,संख्याज्ञान, तार्किकता, समस्या समाधान, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक मूल्यों के विकास के द्वारा सम्भव किया जा सके। ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य की खोज भारत के प्राचीनतम शिक्षा पद्धतियों के आधार हैं जिनकी लौ के प्रकाश में नई शिक्षा पद्धति का ढांचा बहुत संयम और धैर्य से बिल्कुल वैसे ही गढ़ा जा रहा है जैसे कि एक मूर्तिकार अपनी छेनी की हल्की-हल्की चोट पहुंचा कर एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। भारत को सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है कि भारत का युवा देश की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं, देश की कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ठोस ज्ञान प्राप्त करे। आजीविका और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों के कारण ये आवश्यक है कि देश का युवा इतना सक्षम हो कि विश्व पटल पर उसके आत्मविश्वास के सधे पांव कभी

लड़खड़ाएं नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्यतः 4 भाग हैं और इसके कार्यान्वयन की पूर्णता का लक्ष्य वर्ष 2030 है ताकि वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में वर्ष 2030 तक सभी के लिए सार्वभौमिक, गुणवत्तायुक्त सतत शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

ये चार भाग हैं- स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वयन की रणनीति। स्कूल शिक्षा में मुख्य परिवर्तन ये किया जा रहा है जिसमें वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नए शैक्षणिक और पाठ्यक्रम के आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाएगा। 3 से 5 वर्ष तक फाउंडेशनल, अगले 3 वर्ष प्रीपेरटरी, अगले 3 वर्ष मिडिल और अंतिम चार वर्ष सेकंडरी ढांचे को दिए जाएंगे। 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-भाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को इस नई शिक्षा नीति में शामिल किया जा रहा है, जिससे कि सही दिशा में सीखने की सही नींव डाली जा सके। द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय पुस्तकालयों में सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे बाल्यकाल से ही पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त भी अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत का विकास हो सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या घटाना और सभी स्तरों पर शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षण, शिक्षकों के लिए नए निर्णय, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, स्कूल की शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य युवा को समाज और देश की समस्याओं के लिए प्रबुद्ध, जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है ताकि युवा नागरिकों का उत्थान कर सकें और समस्याओं के सशक्त समाधान ढूंढ़ कर और उन समाधानों को कार्यान्वित करके एक प्रगतिशील, सुसंस्कृत, उत्पादक, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयामों की ओर ये नई शिक्षा अग्रसर होती है जिसमें मुख्य हैं-गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय,संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहु- विषयक शिक्षा, सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण और छात्रों को सहयोग, प्रेरणादायक, सक्रिय और सक्षम संकाय, शिक्षा में समता का समावेश, भविष्य के अध्यापकों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन रूप, गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व। वर्तमान शिक्षा प्रणाली और आजीविका और धनार्जन की सक्षमता का एक मापदंड अंग्रेजी भाषा भी है, जो कि देश के अधिकांशतः युवा वर्ग के आत्मविश्वास की कमर तोड़ कर रख देता है और किसी न किसी पटल पर उनको कमतर साबित कर देता है, चाहे वो युवा कितना भी ज्ञान से भरा हुआ क्यों न हो।

प्रदेश में झाबुआ जैसे जल संरक्षण की दरकार

भरत लाल पांडेय
उन्नत किसान

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में सन 1987 से भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे नीलेश देसाई को इस वर्ष के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जमनालाल बजाज प्रतिष्ठान के डाक्टर आरए माशेलकर और शेखर बजाज ने कहा कि नीलेश को सन 2022 का पुरस्कार देते हुए प्रतिष्ठान गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि निलेश ने सृजनात्मक कार्य के श्रेणी में असाधारण काम तीन से ज्यादा दशकों से किया और देश के अति पिछड़े इलाके में एक मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल की संपूर्ण मप्र में दरकार है।

इस पुरस्कार में दस लाख रुपए के साथ प्रतीक चिन्ह और प्रमाणपत्र दिया जाता है। झाबुआ कई लोगों कि कर्मभूमी रही है और आज जो अति पिछड़े आदिवासी नए रंग- रूप और स्वरूप में दिखते हैं उसके लिए कई लोगों का अनथक प्रयास रहा है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद का जन्म भी यहीं हुआ था। मामा बालेश्वर दयाल जैसे समाज कर्मियों से लेकर साधना खोचे, हेर्विग स्ट्रीब्यूल और पद्मश्री जनक पलटा की भी यह जिला कर्मभूमी रही है। इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क से एमएसडब्ल्यू करने के बाद निलेश देसाई, जो मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं, तिलोनिया (अजमेर) चले गए और वहां पर अरुणा राय की संस्था में समाज विज्ञान का ककहरा सीखा। तीन वर्ष तक सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर पर अलग-अलग तरह के काम किए और उस दौरान वे कई तरह के समुदाय और संस्थाओं के साथ मिले। भारत सरकार ने उस समय 10 जिलों को पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए चयनित किया था जहां पर स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से कुछ काम करने का इरादा किया था। सातवें वित्त आयोग के अंतर्गत टेक्नोलॉजी मिशन ने यह काम अपने हाथ में लिया था और बंकर रॉय उस समय योजना आयोग में सलाहकार थे। इन 10 जिलों में काम करने का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की जनभागीदारी से पानी की समस्या का स्थाई हल निकाला जाए और पानी के संरक्षण का काम किया जाए। बरसात की एक भी बूंद कहीं पर बह न जाए यह प्रयास किया जाना था। मप्र का झाबुआ उनमें से एक जिला था। 1987 में यह काम आरंभ हुआ और झाबुआ की रैंकिंग सूखे प्रभावित जिलों में थी जहां मुख्य रूप से पहाड़ों और डूंगर वाला इलाका था। कई प्रकार की चुनौतियों के साथ पानी बचाने का काम शुरू हुआ। उस दौरान नीलेश ने देखा कि यहां पर भील-भिलाला समुदायों के साथ काम करने का अलग अंदाज भी है और बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। पूरे इलाके में शोषण भयंकर है, सरकारी- गैर सरकारी स्तर पर तो है ही, साथ ही छोटे-छोटे गांव और कस्बों में व्यापारियों का एक संगठित नेटवर्क है जो इनका शोषण करता है। राजस्थान में संस्थाओं के काम करने के लिए बहुत अच्छा माहौल है, परंतु मप्र जैसे पिछड़े इलाके में उस समय भी और अभी भी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए माहौल नहीं था। काम की शुरुआत हुई तो लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल था। लोग अक्सर इन लोगों को देखकर जंगलों में भाग जाते थे और बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। नीलेश और उनके कुछ मित्रों ने देखा कि यहां पर तेजाजी उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाते हैं और तेजाजी जयंती के दौरान गांव-गांव में मेले लगते हैं। बस उन्होंने इसी आइडिया को पकड़कर अपने काम की शुरुआत की और सभी मेलों में पानी संरक्षण के छोटे-छोटे स्टॉल लगाना शुरू किए। इसका बड़ा फायदा हुआ और लोग जुड़ने लगे, क्योंकि पानी उनके जीवन से भी जुड़ा था। नीलेश और उनके मित्रों ने नुक्कड़ नाटक, गीत, पोस्टर, बैनर आदि बनाए जो पानी के संरक्षण को लेकर थे और इनका प्रदर्शन बड़े स्तर पर हर जगह किया। 1990 के आते-आते यह काम बड़ा प्रचलित हुआ और इसकी वजह से पानी स्थानीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बना जिसमें समुदाय के लोगों के साथ- साथ प्रशासन भी जुड़ा। 1990 में संपर्क संस्था का सोसायटी एक्ट में पंजीयन हुआ और इस तरह से संस्था का काम विधिवत आरंभ हुआ। गांव का पानी गांव में जैसा नारा लगाकर जो काम शुरू हुआ था उससे खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए आयाम भी जुड़े, सीड बैंक की शुरुआत हुई और 1994 में शिक्षा का पहली बार कोई प्रोजेक्ट मिला। इसमें ऐसे बच्चे आकर जुड़े जो अपनी पीढी के पहले बच्चे थे जो सीधे-सीधे शिक्षा से जुड़े थे, अभी भी नुक्कड़ नाटक समुदाय को जोड़ने का सशक्त माध्यम था। संपर्क संस्था का काम फैलने लगा और संपर्क ने रायपुरिया और पेटलावद के बीच में 7 बीघा जमीन खरीदी और यहां पर एक छोटा सा प्रदर्शन क्षेत्र बनाया और अपना ऑफिस शुरू किया। शुरुआत में लोगों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा परंतु धीरे-धीरे लोगों को समझ में आया कि यह उनके लिए ही है और उनके फायदे के लिए ही संस्था काम कर रही है। संपर्क ने गांव में लोगों के ग्राम कोष बनाए जिससे करीब करीब 70,0000 रुपए समुदाय के पास अपना था जिससे वे आपस में लेनदेन करते थे और इस तरह से ब्याज बट्टा करने वालों का हस्तक्षेप खत्म हुआ और वे लोग एक तरह से संपर्क से जलन रखने लगे।

जनता समझेगी राजनीतिक रेवड़ी बनाम जन-कल्याण

यह महज संयोग है कि आजादी के अमृत महोत्सव की बेला में राजनीतिक रेवड़ी पर जो सियासी रार छिड़ी है, उससे जल्द अमृत निकलने वाला है। सियासी गलियारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक खैरात बनाम लोक कल्याण पर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान अब राजनीतिक खैरात बनाम लोक कल्याण में अंतर तलाशने की आवश्यकता महसूस हुई है और सर्वोच्च अदालत ने इस अंतर को समझने के लिए विशेषज्ञों का पैनल तक बनाने का सुझाव दिया है। सभी पक्षकारों से राय मांगी गई है। यहां यह याद दिला देना भी जरूरी है कि इससे पहले 2013 में तमिलनाडु के मामले में राजनीतिक खैरात को सुप्रीम कोर्ट ने ही जायज ठहराया था। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि यदि सरकार बनी तो बिहार में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगेगी। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनी और वहां कोरोना के टीके मुफ्त लगे। शुरुआत बिहार से हुई। मुफ्त कोरोना वैक्सीन का यह बिहार मॉडल धीरे-धीरे समूचे देश में लागू हो गया। दरअसल देश में 200 करोड़ कोरोना टीके लग चुके हैं, जिनमें से औसतन 150 करोड़ टीके मुफ्त लगे हैं। इस पर केंद्र को अपने स्वास्थ्य बजट में अलग से 35 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा था। सवाल उठता है कि क्या यह राजनीतिक खैरात थी या जन कल्याण। केंद्र के खजाने पर यह जो वित्तीय बोझ था, क्या वह जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता द्वारा नहीं माना जाना चाहिए। जाहिर है आपदा की इस घड़ी में करोड़ों जरूरतमंदों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन राजनीतिक खैरात की श्रेणी में कतई नहीं, क्योंकि इस मुफ्त खुराक से करोड़ों आमजनता की जानें बचीं, इम्युनिटी बढ़ी, वह भी तब जब अस्पतालों में बेड-ऑक्सीजन के लाले पड़ गए थे। इसी कोरोना महामारी के दौरान एकाएक 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। कल-कारखाने,दफ्तर आदि बंद हो गए। रोजी-रोजगार पर संकट खड़ा गया। लाखों मजदूर घर-बार पैदल लौट पड़े। तब घरों में खाली हाथ लौटे करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन क्या खैरात की श्रेणी में मानी जाए। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना के सिक्के का एक पहलू यह था कि गांवों तक घरों में गैस चूल्हे जलने लगे। दूसरा पहलू यह भी था कि गांव से शहर तक के गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करनी पड़ी और जेब पर बोझ बढ़ गया। इस योजना को शायद इसलिए सरकारी खजाने पर बोझ नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यहां भी जनता के पैसे का ही जरूरतमंद जनता के लिए इस्तेमाल हुआ। एक तरफ सब्सिडी बंद हुई, तो दूसरी मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। पहले स्वेच्छिक गैस सब्सिडी बंद की अपील का असर दिखा, लेकिन आपदा के दौरान आर्थिक खाई पाटने सभी गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी गई। इससे कहीं खुशी तो कहीं गम का आलम दिखा।

वर्षा का धान को इसका पूरा फायदा मिले, इसके लिए पानी को रोकें

धान के लिए राहत की बारिश दलहनी को हो रहा नुकसान

- धान की फसल की जरूरत के मुताबिक पानी-खाद की पूर्ति समय पर करें
- दलहनी-तिलहनी फसलों में पानी का भराव न हो, इसका की पूरा ध्यान रखें
- खासतौर पर समतल जगह पर लगी फसलों में पानी का भराव नहीं होने दें

जबलपुर। जबलपुर जिले समेत महाकोशल में हुई झमाझम वर्षा ने भले ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं, पर किसानों के लिए यह राहत भरी थी। खासतौर पर उन किसानों के लिए जिन्होंने इस समय खेत में धान की फसल ली है। कृषि विज्ञानिकों की माने तो इस वर्षा से धान को नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ है। इस समय धान को पर्याप्त पानी की जरूरत है और यह जरूरत वर्षा ने पूरी कर दी। हालांकि, वर्षा से दलहनी और तिलहनी फसलों को थोड़ा नुकसान है, वो भी उन फसलों को जो समतल जगह पर लगाई गई हैं। क्यारीनुमा जमीन पर लगी फसलों को नुकसान नहीं हुआ है। इस नुकसान की भरपाई पिछले दो दिनों से वर्षा न होने की वजह से हो गई है।

धान को पानी की जरूरत

जवाहरलाल कृषि विवि के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रो.दिनकर शर्मा बताते हैं कि पिछले दिनों लगातार दो दिन तक हुई वर्षा से किसानों को नुकसान कम, राहत ज्यादा मिली है। यह समय धान को पानी की जरूरत है और इस पानी की भरपाई 48 घंटे में हुई 6 इंच वर्षा से पूरी हो गई है। जहां तक दहलनी और तिलहनी फसलों की बात करें तो इसमें मामला सामान्य हैं। जिन किसानों ने समतल जमीन पर दलहनी और तिलहनी फसलों को लगाया था, वहां पानी का भराव होने से नुकसान हुआ है, लेकिन कई किसानों से समय रहते इस पानी को निकाल दिया। वहीं कई किसान ने मेड और क्यारीनुमा जगह पर दलहनी-तिलहनी फसल ली, उन्हें नुकसान नहीं हुआ। दलहनी-तिलहनी की फसल लेने वाले किसानों को सलाह दी गई है कि वे वर्षा के दौरान समय रहते पानी की निकासी करें, ताकि नुकसान न हो।

पिछले दिनों हुई वर्षा से फसलों को नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ। खासतौर पर धान की फसल के लिए यह वर्षा अमृत की तरह रही। वहीं दलहनी और तिलहनी फसलों को भी इतना नुकसान नहीं हुआ। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया, ऐसे कोई क्षेत्र अभी तक सामने नहीं आया, जहां वर्षा से फसलों को नुकसान पहुंचा।
एसके निगम, उप संचालक-कृषि, जबलपुर

वर्षा के पानी को रोकने का प्रयास

किसानों का मानना है कि इस समय फसल के लिए मौसम अनुकूल है। अधिकांश किसानों ने धान की रोपाई का काम पूरा कर लिया है। उनके पौधों को मजबूत बनाने के लिए इस समय हो रही वर्षा अमृत की तरह है। ग्राम बैहर के कृषक प्रकाश शुक्ला ने बताया कि इस समय वर्षा के पानी को खेतों में अधिक से अधिक समय तक रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फसलों को जरूरत के मुताबिक पानी मिल जाए। मूंग-उड़द के लिए भी यह पानी अभी तक फायदेमंद रहा। मूंग-उड़द की फसल जहां लगाई जाती है वहां पानी का बहुत समय तक भराव नुकसान देह होता है, लेकिन अब तक जिले में कहीं भी इस तरह से पानी नहीं गिरा कि खेतों में फसलें डूबने की स्थिति बनी हो। मूंग और उड़द के लिए लगातार झड़ी के रूप होने वाली वर्षा नुकसान देह होती है।

सिंघाड़ा एवं उद्यानिकी खेती पर किसान संगोष्ठी

किसानों को बताया सिंघाड़ा की खेती की खासियत

जबलपुर। जागत गांव हमार

कृषि विभाग पनागर में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के सिंघाड़ा उत्पादकों एवं उद्यानिकी में रुचि रखने वाले कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उपसंचालक उद्यानिकी ने डा नेहा पटेल रहीं। उन्होंने कृषकों को सिंघाड़ा की खेती का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इसकी खेती में प्रति एकड़ पचासी हजार रुपए का खर्च आता है, जिसमें सरकार इक्कीस हजार का अनुदान देती है। उन्होंने बताया कि सिंघाड़ा की प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने किसानों को दस लाख तक की मदद करने की योजना की जानकारी दी। इस अवसर पर पनागर के पास बम्होनोदा स्थित सिंघाड़ा प्रसंस्करण इकाई का किसानों को अवलोकन कराया गया। जहां सिंघाड़ा के उत्पाद आटा, अचार, पापड़, लड्डू, चिप्स, नमकीन बनाये जाते हैं। भारत कृषक समाज के केके अग्रवाल एवं रूपेंद्र पटेल ने किसानों से कहा कि अब विभाग से योजनाएं निकलवाने के प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर कृषि विवि के बोर्ड मेंबर डॉ. बीडी अर्जरिया ने सिंघाड़ा उत्पादन में रोगों की जांच व किसानों को उच्च तकनीक उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बीबी पटेल, आरएम पटेल, जितेंद्र देसी, महेंद्र कुर्मी, सुरेश कुर्मी, सिंघाड़ा उत्पादक संघ के दुर्गेश कुशवाहा, दशरथ मांझी आदि मौजूद रहे।

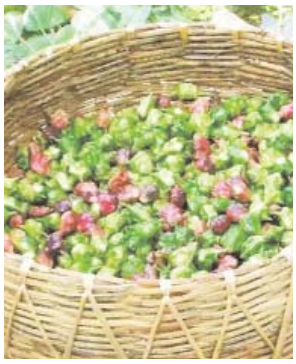

एक जिला-एक उत्पाद में जबलपुर मटर का चयन

जबलपुर जिले में एक जिला-एक उत्पाद के तहत हरी मटर का चयन किया गया है। शहर में लगभग 31 हजार हेक्टेयर में मटर का उत्पादन कर किसानों द्वारा बोरियों में भरकर इसे मंडी प्रांगण में बेचने लाया जाता है। हरी मटर की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए जबलपुरी मटर की ब्रांडिंग के लिए लोगो का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क में किया गया है। इसको लेकर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा ने समस्त मटर व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले की स्थानीय मंडियों में मटर की बोरियों पर जबलपुरी मटर के लोगो का प्रिंट कराकर स्थानीय कृषकों को उपलब्ध कराने कहा है। वहीं मटर के व्यापारियों द्वारा मंडी में जबलपुरी मटर का लोगो लगी हुई बोरियों में ही मटर भरकर जिले से अन्य जिलों एवं राज्यों को विक्रय के लिए भेजने कहा।

वैज्ञानिकों ने विकसित की करेमुआ साग की नई किस्म

'काशी मनु' एक बार लगाने पर लंबे समय तक उत्पादन

भोपाल/वाराणसी। जागत गांव हमार

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी के वैज्ञानिकों ने करेमुआ की नई किस्म, काशी मनु विकसित की है, जिसे एक बार लगाकर कई बार उत्पादन पा सकते हैं। काशी मनु को विकसित करने वाले भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राकेश कुमार दुबे बताते हैं कि पहले करेमुआ बरसात के दिनों में तालाब और नदियों के किनारे जहां पर पानी होता था वहीं पर होता था, क्योंकि पहले इसकी कोई किस्म नहीं थी, इसलिए अपने आप उग जाती थी, उसे ही लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन तालाब-पाखरों में उगने वाले करेमुआ के कुछ नुकसान भी थे, क्योंकि ऐसे में होता था कि पानी में कई तरह के प्रदूषण होते हैं, क्योंकि यह पत्तेदार सब्जी है और इसकी पत्तियां ही खाने में इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा अगर बहुत ज्यादा पानी भरा है तो उसकी हार्वेस्टिंग करना मुश्किल होता था, इसके ध्यान में रखकर हमने इस किस्म को विकसित किया है। इस किस्म की सबसे खास बात यह है कि इसे दूसरे पत्तेदार सब्जियों की तरह से खेत में ही उगाते हैं। इसे तालाब-पोखरों में लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसकी खास बात ये है इसे महीने में तीन से चार बार काट सकते हैं, इसे जितना काटते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। इसे एक बार लगा देंगे ये सालों साल चलती रहेगी और इसके साथ-साथ इसमें पोषक तत्व की भी भरपूर मात्रा होती है, इसमें जिंक, आयरन और एंटी ऑक्सीडेंट की मात्रा भी भरपूर होती है।

राज्यों में मिले अच्छे परिणाम- मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, अयोध्या, बांदा, कुशीनगर जैसे से कई जिलों में किसानों को काशी मनु के बीज दिए गए और इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं।

फायदे की फसल

साग का औसत दाम 15-20 प्रति किलोग्राम होता है। इस हिसाब से किसान की आय हर साल 12,000,000/ से लेकर 15,00,000 प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। कुल मिलाकर यह किसानों के लिए काफी फायदे की फसल है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम लगती है, लेकिन उत्पादन बढ़िया मिलता है।

रोग-कीट भी नहीं लगते

दूसरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक-मेथी की खेती सर्दियों में होती है, जिसमें 3-4 महीनों में फूल आ जाते हैं, लेकिन काशी मनु के साथ ऐसा नहीं है। गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों का आभाव रहता है, इसकी खास बात यह है, जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है वैसे-वैसे इसकी पैदावार भी अच्छी होती है, बरसात में भी ये तेजी से बढ़ते हैं। सबसे खास बात ये है इसमें रोग-कीट भी नहीं लगते हैं।

पानी भी लगता है कम

अगर किसान इस किस्म की खेती करना चाहते हैं तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी से इसके बीज ले सकते हैं। इसकी बोवनी मेड़ पर या क्यारी बनाकर लाइन में की जाती है। एक बार लगा देने पर कटाई चलती रहती है। इसमें पानी भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है। गर्मियों में 15 दिन में सिंचाई की जरूरत होती है।

बेपटरी जिंदगी

बाढ़ से प्रभावित 39 गांवों में लापरवाही की आपदा

चंबल और पार्वती में आए उफान से जिले के 39 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। हालांकि, इन गांवों में प्रशासन की सचेत रहते कोई जनहानि, पशुहानि नहीं हुई, लेकिन धन की हानि आपार हुई है। प्रशासन ने रेस्क्यू चलाकर लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन यह रेस्क्यू आग लगने पर कुएं खोदने जैसा ही चरितार्थ साबित हुआ। लोगों का कहना है कि जिन गांवों में रेस्क्यू किया गया, अधिकतर वह गांव प्रशासन की विस्थापन सूची में दर्ज है। अगर यह गांव विस्थापित हो जाते थे तो लोगों की जान बचाने के लिए शासन-प्रशासन को इतनी कवायद नहीं करनी पड़ती।

श्योपुर। जागत गांव हमार

3 अगस्त 2021 को आई बाढ़ के बाद प्रशासन ने 28 गांवों की सूची तैयार की थी। उक्त गांवों को डूब क्षेत्र में बताकर विस्थापन की सिफारिश की गई थी। इनमें से कुछ गांवों को अधिक खतरनाक मानकर तत्काल विस्थापन की जरूरत बताया था। प्रशासन की ओर से विस्थापन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा भी गया था, लेकिन सरकारी उलझनों में उलझकर यह प्रस्ताव कहा अटक गया किसी को मालूम नहीं। इस बार आई बाढ़ में 39 गांव पार्वती और चंबल की चपेट में आए। इनमें से अधिक डूब में वहीं 28 गांव आए, जिन्हें प्रशासन ने निचले क्षेत्र में मानकर विस्थापन की सिफारिश की थी। लोगों का कहना है कि अगर यह 28 गांव स्थाई रूप से विस्थापित हो जाए तो इस तरह की परेशानी से निजात मिल जाएगी और हमेशा बारिश के समय इन गांवों के परिवारों के सिर पर लटकने वाली मौत की तलवार पर हट जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री के पत्र को वन विभाग की ना

बाढ़ के समय जिस सूंडी गांव पर सबसे अधिक खतरा मंडराता है उस गांव को विस्थापन के लिए ग्रामीणों के साथ हुई सहमति के आधार पर वनक्षेत्र की 500 बीघा जमीन सूंडी गांव के बदले दिए जाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मप्र शासन को पत्र भी लिखा था। उक्त पत्र मुख्यमंत्री के माध्यम से वनविभाग को भेजा गया था, लेकिन वनविभाग ने जनहित और केन्द्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री के निर्देशों की

» आग लगने पर कुआं खोदने जैसा चरितार्थ हुआ बाढ़ प्रभावितों के लिए रेस्क्यू अभियान

» डूब क्षेत्र के गांवों का विस्थापन नहीं होना बन रही हर बार परेशानी

तीसरी बार हाइवे पर चली नाव

चंबल में उफान के चलते 22 अगस्त को दांतरदा-सामरसा के बीच पुलिया पर करीब 8 फीट पानी हो गया। इससे कई गांवों का संपर्क सड़क से टूट गया। एसडीओआरएफ ने मोटरबोट से ग्रामीणों को बाहर निकाला। हाइवे पर मोटरबोट चलने का यह पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी दो बार चंबल के रौद्र रूप के चलते हाईवे पर नाव चल चुकी हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि, जिस जगह से प्रशासन ने हाईवे निकाला वह नीचे स्थान पर है, जहां चंबल का पानी जल्द आता है। अगर यह हाइवे सामरसा चौकी के पीछे होता हुआ निकाला जाता तो हाईवे कभी भी पानी में नहीं डूबता। हाईवे के पानी में डूबने से श्योपुर-सवाई माधोपुर मार्ग 4 दिन तक बंद रहा।

सेना ने पहुंचाया बाढ़ पीड़ितों तक भोजन

बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन को वायुसेना की मदद भी लेनी पड़ी। प्रशासन के बुलावे पर श्योपुर पहुंचे वायुसेना के हेलीकॉप्टर सामरसा, बिवपुरी, जावासा सहित एक दर्जन गांवों में भोजन के पैकेट पटके। बाढ़ के समय ग्रामीणों को प्रशासन ने मवेशियों सहित सुरक्षित तो निकाल लिया, लेकिन कुछ लोग चोरी के डर से घरों पर ही रह गए। छत पर फंसे इन ग्रामीणों को भोजन भेजने का काम सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया।

बिना बारिश के भी टापू बन गया श्योपुर

पार्वती और चंबल में आई बाढ़ की वजह से श्योपुर-कोटा, श्योपुर-सवाई माधोपुर एवं श्योपुर-बारां मार्ग का संपर्क कट गया। इससे राजस्थान में आना-जाना बिल्कुल बंद हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि इन दिनों श्योपुर में ऐसी बारिश नहीं हुई, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो। बिना बारिश के भी श्योपुरवासियों को बाढ़ का कहर मालवा और राजस्थान में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से झेलना पड़ा। पार्वती में बाढ़ मालवा में हुई बारिश की वजह से आई तो चंबल का रौद्र रूप कोटा बैराज से अत्याधिक मात्रा में छोड़ा गया पानी की वजह से देखने को मिला।

तीन दिनों बाद उतरा पानी तो दिखा बर्बादी का असर

चंबल और पार्वती का जलस्तर जिस तरह एक साथ बढ़ा था, उसी तरह एक साथ घट भी गया। तीन दिन बाद बाढ़ का प्रकोप तो समाप्त हो गया, लेकिन वह अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशां छोड़ गई, जिससे ग्रामीणों को उबरने में कई साल सकते हैं। गांवों में सबसे अधिक नुकसान कच्चे घरों का हुआ हैं। जिन गांवों में नदियों का पानी घुसा था वहां पर कच्चे घर तहस-नहस हो गए हैं। पक्के मकानों में रखा अनाज व गृहस्थी का सामान भीगकर बर्बाद हो गया। गांवों में वापस लौट रहे ग्रामीणों को अब भीग चुके अनाज की बदबू परेशान कर रही हैं। जिस अनाज को किसानों ने अपने खून-पसीने से सींचकर तैयार किया था, उसे ही वह कचरा मानकर चंबल और पार्वती में बहा रहे हैं।

बाढ से नुकसान का सर्वे शुरू

बाढ़ से प्रभावित गांवों में जो नुकसान हुआ है,उसका सर्वे करने के लिए प्रशासन ने सर्वे दलों का गठन कर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर गठित किए गए सर्वे दलों में सर्वे दलों में पटवारी सहित अन्य पटवारियों, आरएईओ तथा पंचायत सचिवों को शामिल किया गया है। जबकि निगरानी के लिए नायब तहसीलदार राघवेन्द्र कुशवाह एवं भारतेन्दु सिद्धार्थ गौतम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सहायक नोडल के रूप में आरआई श्रीपाल अपोरिया एवं रामप्रसाद बरेलिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वे दलों में शामिल अमला प्रभावित गांवों में पहुंचकर रहवासी मकानों एवं फसल क्षति सहित आदि के नुकसान के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी जुटा रहा है। सर्वे दल में शामिल अमला प्रभावित गांवों में पहुंचकर सात दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद प्रभावित लोगो को मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू होगी।

सालाना 4 करोड़ के कारोबार से विकसित हुई कड़कनाथ अर्थव्यवस्था

जीआई टैग मिलने से कड़कनाथ के आए अच्छे दिन

-आदिवासियों को उचित तौर-तरीकों को लेकर प्रशिक्षित भी किया गया

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के झाबुआ मूल का कड़कनाथ मुर्गा डेढ़ दशक पहले विलुप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नस्ल बचाने के वैज्ञानिक प्रयासों और जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स (जीआई) का अहम तमगा मिलने के बाद इसके दिन बदल गए हैं। काले रंग के पौष्टिक मांस के लिए मशहूर यह कुक्कुट प्रजाति इस आदिवासी बहुल जिले से निकलकर देश के अधिकांश हिस्सों में फैल चुकी है। झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के प्रमुख डॉ. आईएस तोमर ने बताया कि इन दिनों देश के लगभग हर राज्य के कुक्कुट पालन केंद्रों के संचालक कड़कनाथ मुर्गे की शुद्ध नस्ल के चूजों के लिए झाबुआ की अलग-अलग हैचरी का रुख कर रहे हैं। वहीं कुक्कुट उद्योग के जानकारों के मुताबिक, इन गुणों के चलते देश भर में बढ़ती मांग ने झाबुआ में कड़कनाथ अर्थव्यवस्था विकसित कर दी है और आदिवासी बहुल जिले में इसके चूजों, अंडों और मुर्गों से संबंधित कुल वार्षिक कारोबार चार करोड़ रुपए के आस-पास पहुंच चुका है।

दूसरी प्रजातियों के चिकन के मुकाबले कड़कनाथ में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल

2.5 लाख पैदा वार हर साल

मांग में इजाफे के चलते झाबुआ में सरकारी, निजी और सहकारी स्तर पर कड़कनाथ के चूजों की कुल पैदावार बढ़कर 2.5 लाख के वार्षिक स्तर पर पहुंच चुकी है। केवीके ने सरकार की एक परियोजना के तहत वर्ष 2009-10 में अध्ययन किया, तो पता चला कि मुर्गी पालन के सही तरीकों के प्रति आदिवासियों में जागरूकता के अभाव के कारण तब कड़कनाथ के चूजों की मृत्यु दर काफी अधिक थी।

वजूद पर मंडरा रहा था खतरा

अध्ययन से यह भी मालूम पड़ा कि आदिवासी क्षेत्रों में कड़कनाथ और दूसरी प्रजातियों के मुर्गे-मुर्गियों को साथ रखा जा रहा था, जिससे इसकी संकर नस्लें पैदा हो रही थीं और कड़कनाथ के वजूद पर खतरा मंडरा रहा था। इन तथ्यों के सामने आने पर केवीके ने झाबुआ में अपनी हैचरी शुरू की और कड़कनाथ की मूल नस्ल को बचाने तथा इसे बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया।

1.5 किलो की कीमत 1000-1200 रुपए

झाबुआ में कड़कनाथ के उत्पादन से जुड़ी एक सहकारी संस्था के प्रमुख विनोद मेड़ा ने कहा कि हम देश भर के राज्यों के लोगों के साथ हर साल 20 से 25 लाख रुपए का कारोबार कर लेते हैं। इन दिनों करीब 1.5 किलोग्राम वजन का एक कड़कनाथ मुर्गा 1,000 से 1,200 रुपए के बीच बिक रहा है, जबकि पांच साल पहले यह मुर्गा 500 से 800 रुपए के बीच बिकता था।

जीआई टैग मिलने के बाद बदले दिन

गौरतलब है कि घरेलू बाजार में झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे की प्रामाणिकता को तब बल मिला, जब देश की जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री ने वर्ष 2018 में मांस उत्पाद तथा पोल्ट्री एवं पोल्ट्री मांस की श्रेणी में कड़कनाथ चिकन के नाम भौगोलिक पहचान (जीआई) का चिह्न पंजीकृत किया था। झाबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय जुबान में कालामासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है। कड़कनाथ प्रजाति के जीवित पक्षी, इसके अंडे और इसका मांस दूसरी कुक्कुट प्रजातियों के मुकाबले महंगी दरों पर बिकता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया आह्वान

गरीबों को पशुपालन के लिए करें प्रोत्साहित

दुग्ध सहकारी समितियों के दो लाख से अधिक सदस्यों को मिले क्रेडिट कार्ड

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को 2 लाख 19 हजार 603 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश में 716 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं। इनमें से 336 समितियों में स्व-चालित इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। नाना जी देशमुख पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जबलपुर और डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में डेयरी साइंस और फूड टेक्नॉलाजी पाठ्यक्रम की मंजूरी दी गई है। जबलपुर में गोबर से सीएनजी उत्पादन संयंत्र के लिए कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी, शैलेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बकरी पालन आर्थिक रूप से फायदेमंद - मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीब परिवारों के आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा बकरी पालन कार्य के लिए अधिक से अधिक सहयोग देने के प्रयास किए जाएं। कम स्थान में कम लागत के साथ चारे की उपलब्धता के कारण बकरी पालन आर्थिक रूप से फायदेमंद है। योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता से किया जाए। पशुओं के रोगों के नियंत्रण के लिए विभाग का अमला सजग रहे। जानकारी दी गई कि प्रदेश में बकरी पालन के प्रोत्साहन के लिए हितग्राहियों को आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। उज्जैन, सिवनी, ग्वालियर और टीकमगढ़ में बकरी प्रक्षेत्र के संचालन में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। इन प्रक्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान और वत्सोत्पादन के कार्य में सफलता मिली है।

गौ शालाएं आजीविका का साधन बनी | मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना में मनरेगा में 3 हजार 241 गौशालाएं मंजूर की गई थीं। इनमें से 1033 गौ शालाएं शुरू हो गई हैं। महिला स्व-सहायता समूह की बहनें 530 गौशालाओं का संचालन कर रही हैं। इन्हें गोबर एवं गौमूत्र के विभिन्न उत्पाद जैसे गोबर के गणेशजी, दिए, हवन के कंडे और विभिन्न प्रकार की जैविक खाद के साथ ही अन्य सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौ वंश के संरक्षण के साथ ही गौ शालाएं आजीविका का साधन भी बन गई हैं।

जबलपुर में गोबर से सीएनजी उत्पादन संयंत्र

मुख्यमंत्री ने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए पूर्व में लिए गए निर्णय और की गई कार्रवाई की भी जानकारी प्राप्त की। जानकारी दी गई कि योजना का विभागीय अधिकारियों की समिति ने आकलन कर विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। गोबर से सीएनजी एवं जैविक खाद उत्पादन के लिए लगभग बीस करोड़ रुपए की लागत से पायलट आधार पर जबलपुर में संयंत्र प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य में जबलपुर स्मार्ट सिटी मिशन का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। आगर मालवा जिले के गौ अभयारण्य सालरिया में संचालन के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था को दायित्व सौंपा गया है।

सरकार ने खोला खजाना

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 14 हजार 157 हेक्टेयर में चारा उत्पादन कार्य के लिए कार्ययोजना मंजूर की गई है। इसका लाभ 55 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। इसी योजना में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। डिंडोरी में मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम के लिए इस वर्ष 19 करोड़ 10 लाख रुपए राशि का अनुमोदन हुआ है। इसका लाभ 2 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा।

श्योपुर में लगाए गए सलई के 7500 पौधे, उग रहा जंगल

श्योपुर। जंगल पर निर्भर सहरिया वनवासियों की आय का मुख्य श्रोत माने जाने वाला सलई का पेड़ धीरे-धीरे कर जंगल से कम हो रहा है। यही वजह है कि वन विभाग इससे चिंतित है और जब उसे सीएसआर फंड से तीस लाख रुपए मिले तो, सबसे पहले उसने सलई का जंगल लगाया है। इसके लिए खाड़ी रैंज के टर्राकला क्षेत्र में 25 हेक्टेयर जमीन का चयन करते हुए उसपर सलई के 7500 पौधे लगाए गए हैं। जो अगले आठ-दस साल के भीतर पेड़ बनकर सलई का पूरा जंगल बन जाएगा। खास बात यह है कि सलई का जंगल लगाने का कार्य 2020 में जब कोरोना की लहर शबाब पर थी, तब उसके द्वारा जमीन का चयन करते हुए सलई का जंगल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सामान्य वन मंडल श्योपुर को गुजरात की कंपनी फ्रोजा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह तीस लाख सीएसआर के तौर पर दिए गए।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)